NLM Release	State Release	Total	Releases	Expcnditure-	Unspent Balance (Rs. in lakhs)
Total Litecpcy Campaigns					
48,366.02	19,960.94				
Post Literacy Camp.aigns			68,326.96	51,934.59	16,187.37
11,096.56	4,888.41				
			15,984.97	11,304.04	4,657.17

(c) The targets and achievemenfss under National Literacy Mission are not fixed on annual basis. The National Literacy Mission aims at imparting functional literacy to 100 million non-literates in the age group 15-35 year. 68.57 million persons have since been made literate under various schemes of National Literacy Mission. The Government has taken up several initiatives to achieve these objectives:—

(I) Ensuring a greater role for the State Governments by revitalization of State Literacy Mission Authority.

(ii) Close and more intensive monitoring by holding monthly monitoring meetings.

(iii) More objective evaluation and introducing concurrent as well as external evaluation by an agency within the State and outside the State, respectively.

(iv) Greater involvement of Panchayati Raj Institutions.

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा प्रसिद्ध इतिहासकारों को सौंपा गया अनुसंधान कार्य

3466. **डा. महेश चन्द्र शर्मा**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा प्रो. रोमिला थापर, प्रो. बिपिन चन्द्र, श्री के. एम. श्रीमाली तथा पार्थ सारथी गुप्ता को सौंपे गये अध्ययन और अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है,

(ख) इन कार्यों को निश्चित अवधि में पूर्ण होने या पूर्ण न होने की क्या स्थिति है, और

(ग) इन कार्यों पर परिषद द्वारा कुल कितना खर्च किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1972-73 में प्रो. रोमिला थापर को एक परियोजना "हिस्टा रिकल एटलस ऑफ गंगा एंड युमना दो आव" के लिए 25,000/- की राशि स्वीकृत की गई थी। यह परियोजना पूर्ण हो गई है।

प्रो बिपिन चन्द्र को वर्ष 1987-88 में "ए हिस्टरी ऑफ इंडियन नेश्नल कांग्रेस" नामक कार्य के लिए 75,000 रु. की राशि स्वीकृत की गई थी। दिनांक 23.6.89 तक उन्हें 57,500/- रु. की राशि जारी कर दी गई थी। 17,500/- रु. की बकाया राशि अभी जारी की जानी हैं क्योंकि इससे संबंधित एक औपचारिक पांडुलिपि अभी प्राप्त नहीं हुई।

प्रो. के एम श्रीमाली उन दो सम्पादकों में से एक हैं जो प्रो. आर. एस. शर्मा तथा प्रो. इरफान हबीब के सामान्य सम्पदाकत्व में एक अनुसंधान परियोजना "डिक्शनरी ऑफ सोशल, इकनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स इन इनडियन इन्सक्रिप्शन पर कार्य कर रहे हैं। यह परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है।

प्रो. पार्थ सरथी गुप्ता ने परियोजना "टुवार्ड्स फ्रीड़स" के एक ग्वंड 1943-44 का सम्पादन किया है। खंड के प्रकाशन के बाद सितम्बर, 1997 में उन्हें 25,000/- रु. का मानदेय प्रदान किया गया।

केन्द्रीय विद्यालय आयुक्त का खाली पड़ा पद

3467. **श्री ईश दत्त यादव**:

श्री रामगोपाल यादव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में आयुक्त का पद काफी समय से रिक्त पड़ा है;

(ख) क्या आयुक्त की नियुक्ति न होने से संगठन का कार्य प्रभावित हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो यह पद कब से खाली पड़ा है और संगठन का कार्य सुचारू रुप से चलाने के लिए यह नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा.मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त का पद 16.5.1998 को रिक्त हुआ। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र उक्त तारीख से उस पद का अतिरिक्त पदभार संभाल रहे हैं। पद को भरने के लिए कार्यवाही पहले ही शुरु कर दी गई हैं।

भीरतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पुनर्गठन का प्रस्ताव

3468. **श्री रामगोपाल यादव**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेलों विशेषकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सारे निर्णय राजनीति से प्रेरित, स्वार्थ एवं ईर्ष्या की भावना से लिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पुनर्गठन करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो इसकी समयावधि क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) भारतीय क्रिकेट संघ को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने हेतु सरकार क्या भूमिका अदा करेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) भारत में क्रिकेट संधों का राष्ट्रीय स्तर का एक खेल परिसंघ (एन.एस.एफ.) है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। बी.सी.सी.आई. एक स्वायत्तशासी संगठन है और इसका गठन इसके निजी अपनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नीति के अनुसार, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंधों के आंतरिक कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करती है।

Financial Assistance to Balwadis and Anganwadis

3469. SHRI J. CHITHARANJAN: SHRI GAYA SINGH:

WiU the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Human Resource Development Ministry have issued any order stopping financial assistance given to balwadis and to reduce tjie number of anganwadis in each block;

(b) if so, the details of the order in this regard; and

(c) what is the number of balwadis and anganwadis in operation at present in kerala?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) It was contemplated to phase out the Balwadis sanctioned under Balwadi Nutrition Programme with effect from 1.4.98. The scheme of Balwadi Nutrition Programme has now been continued till 31.3.2001 in the areas not covered by ICDS Projects. No instructions have been issued to reduce the number of anganwadis in any ICDS Project.

(a) Does not arise.

(b) At present 181 Balwadis and 20123 Anganwadis are in operation in Kerala.

Criteria for Creation of Posts of Vice-Principals in Navodaya Vidyalayas

3470. SHRI RAGHAVJI:
SHRI GOVINDRAM MIRI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(b) the criteria for creation of posts of Vice-Principals in Navodaya Vidyalayas;

(c) the number of posts of Vice-Principals created as yet; details thereof, Vidyalaya-wise;